ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप बजट : प्रो. कांकाणी

बजट एक्सपर्ट

नवभारत ब्यूरो । रायपुर।

आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर प्रो. राम कुमार कांकाणी का कहना है कि मोदी 3.0 सरकार का बजट उनकी पिछली सरकार के ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा है, जिसमें राजकोषीय घाटा 4.9% तक कम हो गया है और 4.5% स्पष्ट दृष्टिकोण में है। बजट ने कृषि क्षेत्र को बहुत जरूरी प्रोत्साहन दिया है, कृषि पर 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिसका उद्देश्य एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की प्रथाओं में लाना और जलवायु अनुरूप फसलों पर ध्यान केंद्रित करना है। बजट का एक प्रमुख आकर्षण विनिर्माण क्षेत्र को दिया गया, जो हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है।

एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

प्रो. कांकाणी का कहना है कि एमएसएमई हमेशा से ही क्रेडिट (ऋण) की कमी से जूझते रहे हैं और बजट ने इन चिंताओं को सीधे तौर पर सुलझाने का प्रयास किया है। बजट में एक क्रेडिट गारंटी योजना पेश की गई है जो एमएसएमई को बिना कोलेटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के मशीनरी खरीदने के लिए टर्म लोन प्राप्त करने की अनुमति देगी। यह एमएसएमई के लिए एक बड़ा कदम है क्योंकि यह उनके कार्यशील पूंजी चक्र को राहत प्रदान करता है।

एफडीआई मानदंडों में सुधारों का वादा- सरकार ने एफडीआई में गिरावट को भी पहचाना है और इसके परिणामस्वरूप एफडीआई मानदंडों को आसान बनाने के लिए सुधारों का वादा किया है, जिससे उम्मीद है कि एफडीआई पहले के स्तर तक पहुंचेगा और यहां तक कि इसमें वृद्धि भी होगी।

कस्टम ड्यूटी में कटौती स्वागतेय

कस्टम ड्यूटी में कटौती, विशेष रूप से मोबाइल पार्ट्स की (15% तक घटाई गई) व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और भविष्य में भारत को एक प्रमुख वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला खिलाड़ी के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है और इस वर्ष की शुरूआत में प्रमुख मध्यवर्ती इनपुट पर आयात शुल्क में कमी के साथ मेल खाता है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों की स्थापना छोटे फर्मों और कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों का आसानी से अन्वेषण करने में मदद करेगी। इससे उन्हें अपना बाजार आधार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में उनके कुल योगदान को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह एक शानदार कदम है, क्योंकि भारत का कुल ई-कॉमर्स निर्यात प्रवेश कम है और यह भारत की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में मदद कर सकता है।

रोजगार और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ने में मदद

सरकार का रोजगार सृजन के लिए 2 करोड़ रुपये का आवंटन समय पर है क्योंकि भारतीय कार्यबल का आकार बढ़ रहा है। इस संदर्भ में, 20 लाख युवाओं के कौशल के लिए सीएसएस कार्यबल को अधिक रोजगार योग्य बनाएगा और विनिर्माण क्षेत्र को भी बढ़ने में मदद करेगा। इसके अलावा एक चीज और जो वेतनभोगी वर्ग की मदद करेगी, वह है मानक कटौती में वृद्धि, साथ ही कर स्लैब का पुनर्गठन। कुल मिलाकर बजट अच्छा और संतुलित है और सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान किया गया।

Navbbharat (my City), 24th july, 2024, P. 01.